(ग) उससे कितने व्यक्तियों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाया गया ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथाउपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़े एकत्र करने की वर्तमान प्रणाली से जमा और अग्रिमों के सम्बन्ध में शाखा वार सूचना प्राप्त नहीं होती है ऐसा महसूस किया जाता है कि अलग बैंकों/शाखाओं से सूचना एकत्र करने में जितना समय और श्रम लगेगा, वह प्राप्त होने वाले उद्देश्य को देखते हुए कहीं अधिक होगा।

Implementation of Liberalised Pension Orders

4652. SHRI. ANWAR AHMED : Will the Minister of FINANCE be pleased to state;

(a) whether Government have implemented the Liberalised Pension Orders in pursuance of the Supreme Court decision;

(b) if so, the categories of beneficiaries;

(c) whether the family pensioners have been covered under these orders;

(d) if not, the reasons therefor;

(e) whether Government propose to extend the above pension orders to the family pensioners also in view of the Supreme Court decision in which all the categories of pensioners were included; and

(f) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S M. KRISHNA) : (a) Yes, sir.

(b) Pensioners in receipt of following types of pension are the beneficiaries:—(1) Retiring Pension (2) Superannuation Pension (3) Compensation Penson (4) Invalid Pension (5) Compassionate Allowance and (6) Compulsory Retirement Pension.

(c) to(f) Family pension is determined on an entirely different basis and not on the basis of the Liberalised Pension Orders of 1979. Therefore, the judgement of the Supreme Court has no relevance to this class of pensioners.

घटिया किस्म के कारण भारत के विदेश व्यापार में गिरावट

4653. **श्री बी. डी. सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के विदेश व्यापार में गिरावट के लिए उत्तरदायी मुख्य कारणों में से एक कारण यह भी है कि भारतीय वस्तुएं घटिया किस्म की होती हैं;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम तथा खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की जांच परिषद द्वारा कराए जाने की बजाए उनकी जांच निजी एजेंसियों द्वारा कराई जाती है;

(ग) क्या भारतीय वस्तुओं की किस्म में गिरावट के लिए यह व्यवस्था भी जिम्मेवार है; और

(घ) इस व्यवस्था में सुधार करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?